

दैनिक जागरण

विकसित भारत का अग्रणी
सेवा, सुधासन, गरीब कल्याण के
11 साल

ऑफ बीट
जापान में 15 करोड़ रुपए
में बिकी एक मछली



कोई मछली अपनी सुंदरता, लाल और सफेद रंगों की बाबत के लिए दुनियाभर में मशहूर है लेकिन सिर्फ इका रंग ही नहीं बल्कि इनका मूल्य भी हैरान करने वाला होता है। इन मछलियों को दुनिया के सबसे महंगी पालतू मछलियों में गिना जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि एक कोई मछली की कीमत 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लग चुकी है? हाल ही में जापान में हुई एक नीलामी में एस लीजेंड नाम की एक कोई मछली ने सबका ध्यान खींचा। यह काकाहू नस्ल की एक मादा मछली थी, जिसके लालीवाले चर 39 इंच थे और उसकी 9 साल। इसे यिग्यिं चुंगान नाम के कोई क्लेवर्टर ने 1.8 मिलियन डॉलर (लगभग 15.5 करोड़ रुपए) में खरीदा। इस मछली को दूसरे संकेत के बाद यात्रा था, जो कि जापान के हिरोशिमा स्थित संकेत किश्याफार्म के मालिक है। दरअसल, इस कोई मछली में एक बार में 10 लाख तक अंडे देने की क्षमता है।

संक्षिप्त खबरें

यूजीसी नेट के 25 से 29 तक होंगे पेपर

नई दिल्ली, जेएनएन। यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने लाखों छात्रों को बड़ी सात देते हुए एक समय में दो डिग्रियां हासिल करने का गत्ता साफ कर दिया है। नियमों में संशोधन के बाद एक ही शैक्षणिक सत्र में प्राप्त दोनों डिग्रियां मात्र होंगी, जो वे रेगुलर या डिस्टेंस मोड में होंगी। यह नियम 2022 से पहले एक साथ प्राप्त की गई डिग्रियों पर भी लागू होगा।

यूजीसी ने अपने दिशानिर्देशों में संशोधन करने के बाद कहा कि पहले अगर कोई विद्यार्थी सत्र में दो डिग्रियों ले लाए था, तो उन डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाती थी इसके बाद 2020 में नियमों में बदलाव किया गया और एक रेगुलर तथा एक डिस्टेंस डिग्री को मान्यता दी गई। अब विद्यार्थी एक साथ दो डिग्रियां हासिल कर सकेंगे और दोनों ही मान्य होंगी। जिन लोगों ने 2022 से पहले एक साथ दो डिग्रियां हासिल की थीं, उन्हें भी मात्र कर लिया गया। इस फैसले से उन छात्रों को विशेष लाभ होगा, जो एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को पूरा करना चाहते हैं।

यूजीसी नेट के 25 से 29 जून के बीच कंप्यूटर बेस्ट ईस्ट यानी सीधी ऑफर के लिए एसिटी एस्ट्रेनिंग में होगा। पेपर से 10 दिन पहले कैम्पिंग ट्रैनिंग के बाद यात्रा शुरू होगी। इसमें मल्टीलैन चाइस क्वर्चर्स के बारे पेपर होंगे। पहले पेपर 100 और दूसरा पेपर 200 मार्क्स की होगा। लैंगेजेज के पेपर के अलावा सभी पेपरों में इंग्लिश और हिंदी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा।

मुझे भ्रष्टाचार के आरोप में फँसाया जा रहा: मलिक

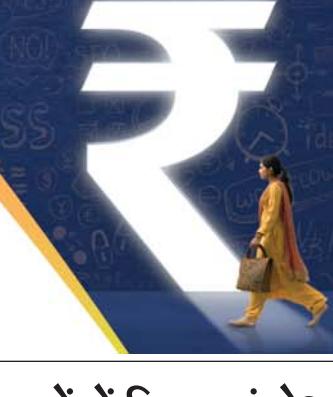
नई दिल्ली, जेएनएन। जम्मू-कश्मीर के किसी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जीसी टाइबिल होने के 15 दिन बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर सरपाल मलिक को तूफ़ी तोड़ी। हालांकि, उन्होंने बाहर गये थे और वे 11 मई से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने शनिवार को एक्स्प्रेस पर जैसे-जैसे को अपने-को खंडन किया। कहा गया था कि उन्होंने को खंडन किया था। उन्होंने जैसे-जैसे को अपनी फैसलों की बाबत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूँ या ना रहूँ इत्तिलाएं अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूँ और आज मेरे पास दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता।

आरक्षण के लिए गुर्जरों की महापंचायत आज

जयपुर, जेएनएन। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आदिलान की पिंज से आहट हो रही है। सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण सहित कई मार्गों को लेकर रिवरवार को भटपूर के पीतूलुरा में महापंचायत का ऐलान किया गया है। गुर्जर आरक्षण संस्थित के अध्यक्ष विजय वैसला ने शनिवार को कहा कि 17 महीने से लगातार सरकार को बता रहा हूँ। चाहे वह मंटी हो, चाहे वह एकीप हो। मैंने सीपी की बिट्टी लिखी। लैंका किए पिंज से आहट हो रही है।

उन्होंने कहा कि रिवरवार को एक रिवरवार को बड़ा सुझाइया करना चाहता है। उन्होंने जैसे-जैसे को अपने-को खंडन किया था। उन्होंने जैसे-जैसे को अपनी फैसलों की बाबत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूँ या ना रहूँ इत्तिलाएं अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूँ और आज मेरे पास दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता।

यूजीसी ने नियमों में किया संशोधन, लाखों स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा
3ब एक साथ किए जा सकेंगे दो कोर्स 2022 से पहले की डिग्रियां भी मान्य



महिलाओं की उद्यमिता को मिला हौसला

35 करोड़ से अधिक लोन के साथ मुद्रा योजना की करीब 70% लाभार्थी महिलाएं



A DREAM RAILIZED!

Amul
TICKET TO GREAT TASTE
कश्मीर को जोड़ने वाला ऐतिहासिक पुल!

भाजपा ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता: राहुल गांधी

चुनाव आयोग बोला-दावा निराधार

नई दिल्ली, जेएनएन। राहुल गांधी चुनावी नतीजों पर भरोसा खत्म हो ने शनिवार को एक अखबार में लिखे जाता है। हर जिम्मेदार भारतीय को एक लेख में कहा, भाजपा और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप्स की चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक साथ दो डिग्रियां हासिल करने की इजाजत देने से यात्रों का बहुत अधिक समय बचाया जाएगा और वे अपने कार्रवाय को चुन पाएंगे। इसके साथ ही आज के दौर में जिस पेशेवर कौशल की जरूरत है, युवा उसे भी अपनी पढ़ाई के साथ हासिल कर पाएंगे। इसका फायदा युवाओं को तो होगा ही, रोजगार-प्रदाताओं को भी होगा, इस समय उद्योग जगत प्रतिभाओं में प्रवेश लिया जाएगा तो यह उसके साथ नहीं होगा।

यूजीसी का यह नया दिशानिर्देश भारतीय उच्च शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो छात्रों को अपनी शैक्षणिक और करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। इस समय युवा अपने करियर को लेकर खास संवेदनशील हो गए हैं। 22 साल की उम्र तक पहुंचते हुए युवाओं को छात्रों वे कुछ न कुछ बहुत जाना चाहते हैं। यूजीसी का मानना है कि एक साथ दो डिग्रियां हासिल करने की इजाजत देने से यात्रों का बहुत अधिक समय बचाया जाएगा और वे अपने कार्रवाय को चुन पाएंगे। इसके साथ ही आज के दौर में जिस पेशेवर कौशल की जरूरत है, युवा उसे भी अपनी पढ़ाई के साथ हासिल कर पाएंगे। इसका फायदा युवाओं को तो होगा ही, रोजगार-प्रदाताओं को भी होगा, इस समय उद्योग जगत प्रतिभाओं की कमी से जु़बा रहा है।

यूजीसी का यह नया दिशानिर्देश भारतीय उच्च शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो छात्रों को अपनी शैक्षणिक और करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। इस समय युवा अपने करियर को लेकर खास संवेदनशील हो गए हैं। 22 साल की उम्र तक पहुंचते हुए युवाओं को छात्रों वे कुछ न कुछ बहुत जाना चाहते हैं। यूजीसी का मानना है कि एक साथ दो डिग्रियां हासिल करने की इजाजत देने से यात्रों का बहुत अधिक समय बचाया जाएगा और वे अपने कार्रवाय को चुन पाएंगे। इसके साथ ही आज के दौर में जिस पेशेवर कौशल की जरूरत है, युवा उसे भी अपनी पढ़ाई के साथ हासिल कर पाएंगे। इसका फायदा युवाओं को तो होगा ही, रोजगार-प्रदाताओं को भी होगा, इस समय उद्योग जगत प्रतिभाओं की कमी से जु़बा रहा है।

यूजीसी का यह नया दिशानिर्देश भारतीय उच्च शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो छात्रों को अपनी शैक्षणिक और करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। इस समय युवा अपने करियर को लेकर खास संवेदनशील हो गए हैं। 22 साल की उम्र तक पहुंचते हुए युवाओं को छात्रों वे कुछ न कुछ बहुत जाना चाहते हैं। यूजीसी का मानना है कि एक साथ दो डिग्रियां हासिल करने की इजाजत देने से यात्रों का बहुत अधिक समय बचाया जाएगा और वे अपने कार्रवाय को चुन पाएंगे। इसके साथ ही आज के दौर में जिस पेशेवर कौशल की जरूरत है, युवा उसे भी अपनी पढ़ाई के साथ हासिल कर पाएंगे। इसका फायदा युवाओं को तो होगा ही, रोजगार-प्रदाताओं को भी होगा, इस समय उद्योग जगत प्रतिभाओं की कमी से जु़बा रहा है।

यूजीसी का यह नया दिशानिर्देश भारतीय उच्च शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो छात्रों को अपनी शैक्षणिक और करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। इस समय युवा अपने करियर को लेकर खास संवेदनशील हो गए हैं। 22 साल की उम्र तक पहुंचते हुए युवाओं को छात्रों वे कुछ न कुछ बहुत जाना चाहते हैं। यूजीसी का मानना है कि एक साथ दो डिग्रियां हासिल करने की इजाजत देने से यात्रों का बहुत अधिक समय बचाया जाएगा और वे अपने कार्रवाय को चुन पाएंगे। इसके साथ ही आज के दौर में जिस पेशेवर कौशल की जरूरत है, युवा उसे भी अपनी पढ़ाई के साथ हासिल कर पाएंगे

संक्षिप्त खबरें

आरक्षक भर्ती की सीबीआई से कराई जाए जांचः कटारे

विशेष संवाददाता, भोपाल। विधानसभा में उपनेता प्रतिवक्ष हमेंत कटारे ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस संबंध में सीएम को कटारे ने पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि व्यापक की तरह पर एक बार फिर से मप्री पुलिस आरक्षक घोटाला में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिसमें प्रदेश के 8 जिलों सहित छठीसगढ़ व बिहार राज्यों के 16 प्रकरणों में अपराध पंजीयन कर दिया जाए। इसके बाद विधायियों को गिरफतार कर विवेचना जारी है। इस पूरे मामले में परीक्षा सम्पन्न करने वाली संघर्ष व उससे जुड़े अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस मामले की जांच पुलिस के बजाय केन्द्रीय जांच एंसेजी से कराई जाए।

देशवासियों के लिए गौरव का क्षण : सीएम

विसं भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे विवाद रेलवे ब्रिज और देश के पलों के बीच संरेख्य पुल का शाखांभूत देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री ने एक संदेश में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में स्थानीय चिनाब रेलवे अत्यधिकारीका तनीकी, बेमिसाल कार्यपालिंग और देश के पलों के बीच संरेख्य पुल का शाखांभूत देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है।

विसं भोपाल। मुख्यमंत्री ने एक संदेश में कहा है कि आर्यों का जनकारी मांगी गई है। पत्र में वेतन आहरिंग नहीं होने वाले कर्मचारियों को डेटा भी संलग्न में पंजीकृत कर्त्ता द्वारा दिया जाए। इस पूरे मामले में परीक्षा सम्पन्न करने वाली संघर्ष व उससे जुड़े अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस मामले की जांच पुलिस के बजाय केन्द्रीय जांच एंसेजी से कराई जाए।

चार माह से प्रदेश के 50 हजार कर्मचारियों का नहीं निकला वेतन, गड़बड़ी की आशंका

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश के 50 हजार नियमित और अनियमित कर्मचारियों का पिछले 4 माह से वेतन आहरण नहीं हो रहा है। इस पर कोष एवं लेखा विभाग ने सभी विभागों से कहा कि 15 दिन में कर्मचारियों का डेटा उपलब्ध कराया जाए। हालांकि वित्त विभाग ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिनमें सेवानिवृत्त के उपरांत वेतन सूची से नाम रखने की प्रक्रिया चल रही है। जनकारी को लेकिन एवं लेखा विभाग के संज्ञान में अलग-अलग विभागों के तकरीबन 40 हजार रेणुलर और 10 हजार नॉन रेणुलर कर्मचारियों को पिछले 4 माह से वेतन आहरण नहीं होने की बात आई। इसके बाद विभाग ने सभी विभागों के कर्मचारियों को लेखा विभाग के बारे में जनकारी मांगी है। पत्र में सफाई तौर पर कहा गया है कि आईएफएमआईएस को दिसम्बर 2024 के बाद से सेवानी टेक्सी से नहीं निकाली गई है। पत्र में वेतन आहरिंग नहीं होने वाले कर्मचारियों को डेटा भी संलग्न में पंजीकृत कर्त्ता द्वारा दिया जाए। इस पूरे मामले में परीक्षा सम्पन्न करने वाली संघर्ष व उससे जुड़े अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस मामले की जांच पुलिस के बजाय केन्द्रीय जांच एंसेजी से कराई जाए।

जानकारों का कहना है कि यह मामला इसलिए जंबीर है क्योंकि जिन कर्मचारियों के वेतन का आहरण नहीं किया जाया है, लेकिन उनके एम्लॉर्डी कोड जेवेट किए जाए हैं। इससे भविष्य में वेतन विभागों की आशंका है। इसी तह सरकार को इस बात का भी संदेह है कि इसने इन कर्मचारियों का वेतन आहरिंग नहीं किया गया है। इसकी 15 दिन के भीतर सप्त रूप से कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। पत्र में यह भी कहा गया कि योद्धा डेटा में संविधान, काल्पनिक या फर्जी कर्मचारी कोड बनाए गए थे या नहीं। इधर अधिकारियों का कहना है कि संविधित कर्मचारियों का वेतन नहीं निकाला जाया, जबकि खातों में राशि जाए है। ऐसे में यह पत्र गड़बड़ी की संभावनाओं को संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के माध्यम से तक्ताल प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाए।



कर्मी फर्जी कर्मचारी कोड तो नहीं बनाए गए

जानकारों का कहना है कि यह मामला इसलिए जंबीर है क्योंकि जिन कर्मचारियों के वेतन का आहरण नहीं किया जाया है, लेकिन उनके एम्लॉर्डी कोड जेवेट किए जाए हैं। इससे भविष्य में वेतन विभागों की आशंका है। इसी तह सरकार को इस बात का भी संदेह है कि इसने इन कर्मचारियों का वेतन आहरिंग नहीं किया गया है। इसकी 15 दिन के भीतर सप्त रूप से कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। पत्र में यह भी कहा गया कि योद्धा डेटा में संविधान, काल्पनिक या फर्जी कर्मचारी कोड बनाए गए थे या नहीं। इधर अधिकारियों का कहना है कि संविधित कर्मचारियों का वेतन नहीं निकाला जाया, जबकि खातों में राशि जाए है। ऐसे में यह पत्र गड़बड़ी की संभावनाओं को तक्ताल प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाए।

सिंधिया बाराती घोड़े, जो सत्ता के आसपास नाचते हैं: पटवारी

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा की सांसदीय आशासन संबंधी विधानसभा ने असम एवं मेघालय राज्य के दौरे के द्वारा देशवासियों के विवाह सम्बन्धी विधानसभा और आशासनों के संसदीय प्रक्रियाओं एवं आशासनों के निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति एवं निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने एवं संविधित द्वारा आशासनों की पुर्ति के काम सम्यक की जाए। इस दिवांग में अध्ययन करने के लिए आयोजित किया गया है। संविधित ने अपेक्षा मेघालय प्रवास के दौरा वाहनों के सौन्दर्यमंत्री कार्यालय संगम स्थल पर पर्यटन का आयोजित किया गया है।

मेघालय सीएम से इंदौर के दंपति मामले पर की चर्चा

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा की सांसदीय आशासन संबंधी विधानसभा ने असम एवं मेघालय राज्य के दौरे के द्वारा देशवासियों के विवाह सम्बन्धी विधानसभा और आशासनों के संसदीय प्रक्रियाओं एवं आशासनों के निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति एवं निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने एवं संविधित द्वारा आशासनों की पुर्ति के काम सम्यक की जाए। इस दिवांग में अध्ययन करने के लिए आयोजित किया गया है। संविधित ने अपेक्षा मेघालय प्रवास के दौरा वाहनों के सौन्दर्यमंत्री कार्यालय संगम स्थल पर पर्यटन का आयोजित किया गया है।

सीएम से इंदौर के दंपति मामले पर की चर्चा

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा की सांसदीय आशासन संबंधी विधानसभा ने असम एवं मेघालय राज्य के दौरे के द्वारा देशवासियों के विवाह सम्बन्धी विधानसभा और आशासनों के संसदीय प्रक्रियाओं एवं आशासनों के निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति एवं निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने एवं संविधित द्वारा आशासनों की पुर्ति के काम सम्यक की जाए। इस दिवांग में अध्ययन करने के लिए आयोजित किया गया है। संविधित ने अपेक्षा मेघालय प्रवास के दौरा वाहनों के सौन्दर्यमंत्री कार्यालय संगम स्थल पर पर्यटन का आयोजित किया गया है।

सीएम से इंदौर के दंपति मामले पर की चर्चा

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा की सांसदीय आशासन संबंधी विधानसभा ने असम एवं मेघालय राज्य के दौरे के द्वारा देशवासियों के विवाह सम्बन्धी विधानसभा और आशासनों के संसदीय प्रक्रियाओं एवं आशासनों के निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति एवं निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने एवं संविधित द्वारा आशासनों की पुर्ति के काम सम्यक की जाए। इस दिवांग में अध्ययन करने के लिए आयोजित किया गया है। संविधित ने अपेक्षा मेघालय प्रवास के दौरा वाहनों के सौन्दर्यमंत्री कार्यालय संगम स्थल पर पर्यटन का आयोजित किया गया है।

सीएम से इंदौर के दंपति मामले पर की चर्चा

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा की सांसदीय आशासन संबंधी विधानसभा ने असम एवं मेघालय राज्य के दौरे के द्वारा देशवासियों के विवाह सम्बन्धी विधानसभा और आशासनों के संसदीय प्रक्रियाओं एवं आशासनों के निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति एवं निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने एवं संविधित द्वारा आशासनों की पुर्ति के काम सम्यक की जाए। इस दिवांग में अध्ययन करने के लिए आयोजित किया गया है। संविधित ने अपेक्षा मेघालय प्रवास के दौरा वाहनों के सौन्दर्यमंत्री कार्यालय संगम स्थल पर पर्यटन का आयोजित किया गया है।

सीएम से इंदौर के दंपति मामले पर की चर्चा

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा की सांसदीय आशासन संबंधी विधानसभा ने असम एवं मेघालय राज्य के दौरे के द्वारा देशवासियों के विवाह सम्बन्धी विधानसभा और आशासनों के संसदीय प्रक्रियाओं एवं आशासनों के निराकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थ

